



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

दो. 136]
No. 136]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 1991/फाल्गुन 13, 1912
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 1991/PHALGUNA 13, 1912

इस भाग में खिल पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पृष्ठ मंत्रालय

प्रधिकारिता

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1991

का. प्रा. 153(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित
प्रादेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

यह: मेरा, प्रार. बैंकटरामन, भारत का राष्ट्रपति, ने 12 जनवरी,
1991 को संघ राज्य भेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) के कानूनी उपबंधों
का प्रत्यंतं पांडितेरी संघ राज्य भेत्र के संबंध में उस तारीख से छह माह
की अवधि के लिए निलम्बित करने का आदेश किया था, और उस संघ
राज्य भेत्र का विवानसभा को निलम्बित करते समय में कानूनी
अनुचालिक और परिणामिक उपबंध किए जो युक्त उपर्युक्त कानूनियि
में उस संघ राज्य भेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंधों
के अनुसार बताने के लिए प्रावधक और संवेदन लगे थे ;

और यह: मूर्ख संघ राज्य भेत्र पांडितेरी के प्रशासक से एक और
रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मेरा यह

समाधान हो गया है कि उक्त संघ राज्य भेत्र में स्थित अभी भी ऐसी
बनी हुई है कि उस संघ राज्य भेत्र का प्रशासन अधिनियम के प्रावधानों
के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

प्रतः, अब अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रबल संबिलयों तथा इस
निमित्त मुक्त समर्थ बताने वाली अम्म सभों शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
मैं एकदृष्टा राज्य भेत्र पांडितेरी का विचान भवा तत्काल प्रबोध से
भंग करता हूं और यह निवेदा देता हूं कि उक्त प्रादेश के प्रावधान, निम्न-
लिखित संस्थानों के अध्यधान लार्ग हों, प्रपत्र :—

(i) उक्त भेत्र के खंड (क) में “धारा 6 की उपस्थान (i)”,
मार्डों, कोष्ठकों और घरों से आरम्भ होने वाले और “धारा
33 और धारा 36” पर संसाधन होने वाले भाग के स्थान पर
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अवश्य :—

“धारा 6 को उपस्थान (1), तथा उपस्थान (2), का खंड (क),
धारा 7, उप धाराएँ (1), (3) तथा (4), उप धारा (2) का खंड
(अ) तथा (अ) और उप उप-व-ए का प्रथम परम्परा, और उप-
धारा (5) का उत्तरा भाग, जितने का संबंध उपाध्यक्ष के बेल
और भत्तों से है ,

धारा 8 से 12 (दोनों सम्मिलित हैं), धारा 15 से 17 (दोनों सम्मिलित हैं),

धारा 23;

धारा 27 को उप-धारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है और उक्त धारा की उप-धारा (3) के बांड (ग) का उतना भाग जितने का संबंध उपायकार्य के बीतन तथा भर्ती से है;

धारा 30 की उप-धारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है,

धारा 33, धारा 34 की उप-धारा (2) और धारा 36;

(ii) बांड (ब) में—

(1) उप-बांड (i) तथा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-बांड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(i) उक्त संघ राज्य क्षेत्र को विद्यानन्दमा एत्युत्तमार्थ भंग को जाएगा।

(2) उप-बांड (iii) की उसके उप-बांड (ii) के रूप में गणना को जाएगी।

मई दिल्ली,
4 मार्च, 1991

इ. /—
(भार. चैकटरामन)
भारत का राष्ट्रपति

[सं. यू-11012/3/90- यू. दी. एल.
एस. वस्त्र, संयुक्त सचिव]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 1991

S.O. 153(E).—The following order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas I, R. Venkataraman, President of India had on the 12th January, 1991 made an Order, suspending for a period of six months the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as “the Act”) in relation to the Union territory of Pondicherry, and while suspending the Legislative Assembly of that Union territory I made certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering that Union territory in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

AND, WHEREAS, I have received a further report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report received by me, I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby dissolve the Legislative Assembly of the Union territory of Pondicherry with immediate effect and direct that the provisions of the said order shall have effect subject to the following modifications, namely :—

(i) in clause (a), for the portion beginning with the words, brackets and figures “sub-section (1) of section 6”, and ending with the words and figures “section 33 and section 36”, the following shall be substituted, namely :—

“sub-section (1), and clause (a) of sub-section (2), of section 6;

in section 7, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

sections 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive);

section 22;

so much of sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the said section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President;

section 33, sub-section (2) of section 34 and section 36;”;

(ii) in clause (b),—

(1) for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(i) the Legislative Assembly of the said Union territory is hereby dissolved;”;

(2) sub-clause (iii) shall be renumbered as sub-clause (ii) thereof.

Sd/-

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT OF INDIA.

NEW DELHI;
the 4th March, 1991.

[N. U-11012/3/90-UTL]
S. DUTTA, Jt. Secy.